

नक्सल प्रभावित बस्तर के घने जंगलों में मीडिया के  
बी. के. शान्ति दूत

लेखक- कृष्ण चन्द्र मौलि

कभी कभी सच का सामना होता है तो भी अविश्वस्नीय सा लगता है। हाल ही में ऐसे ही सच का सामना हुआ। सुदूर बस्तर के जंगलों में बसे एक आदिवासी गाँव बडंजा में ब्रह्मकुमारीज के शान्ति दूत के रूप में जाना हुआ। साथ में 35 और बी.के. शान्ति दूत भी थे। ये शान्ति दूत वास्तव में बी.के. मीडिया ग्रुप के पदाधिकारी और सदस्य थे। इस गाँव की गीता पाठशाला में जो कुछ देखने को मिला वो अच्छे अच्छों को अचरज में डाल सकता है। गीता पाठशाला में ब्रह्मकुमारीज के दर्शन से परिचय कराया जाता है। बडंजा गीता पाठशाला उसी प्रकार की 'शालाओं' में से एक है। इस गाँव में हलबी समुदाय के लोग रहते हैं। इस समुदाय की दोनों लड़कियाँ सुभद्रा और सावित्री बचपन से ही ब्रह्मकुमारीज के दर्शन के प्रति आकर्षित हुईं और ज्ञान में आ गईं। अब वे चेहरा, चलन, पहनावा, और मन वचन और कर्म से ब्रह्मकुमारी हो गईं। उन्होंने हलबी समाज की सभी बुराइयाँ 'शराब, माँस, नशे के अन्य व्यसन त्याग दिये। इन लड़कियों से हुई बातचीत से पता चला कि उनके माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्य और समाज के लोग लगातार लड़कियों के ज्ञान में प्रवेश और गीता पाठशाला जाने का विरोध करते आये हैं। उन्हें मारा पीटा भी जाता रहा है। धमकियाँ भी दी जाती रही हैं। इन सब परेशानियों और कठिनाइयों के बावजूद ये दोनों लड़कियाँ ज्ञान में चलते रहने के प्रति अटल रहीं। जब उनसे प्रश्न किया गया कि इतने विरोध सहने के बावजूद वे ज्ञान क्यों नहीं छोड़ देतीं? एक क्षण की भी देर नहीं करते हुए दोनों ने उत्तर दिया कि यदि सभी ऐसे ही सोचेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता कौन कराएगा? उत्तर सुनकर अच्छे अच्छे ज्ञानी आवाक रह गये। जब ज्ञान की बात चली तो ये दोनों लड़कियाँ लौकिकता, अलौकिकता, देह,

आत्मा, परमात्मा, राजयोग, ध्यान आदि बुनियादी, सैद्धान्तिक बातों की बारीकियाँ समझाने लगीं। पता नहीं ऐसी कितनी सुभद्राएँ और सावित्रियाँ बस्तर के सुदूर जंगलों में बसे दुर्गम गाँवों में शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष कर रही होंगी।



बस्तर के जंगलों में ऐसी 'शक्ति स्वरूप लड़कियों' के होते हुए भी क्या कारण है कि नक्सलवाद जैसी हिंसक प्रवृत्ति को प्राश्रय मिला ? ब्रह्माकुमारीज के 'शान्ति दूतों' के लिए यह एक जिज्ञासा की बात रही। खोजबीन करने का निर्णय लिया गया। अनेक लोगों से बातचीत की गई। कोई भी कुछ खुलकर कहने को तैयार नहीं था। सभी डरे सहमे हुए थे। सभी नाम न लेने की 'शर्त' पर कुछ कहने को तैयार हुए। इन सब कथनों को समेट कर बस्तर में नक्सलवाद पर एक 'शब्द चित्र' प्रस्तुत किया जा रहा है।

आरम्भिक दौर में नक्सलवाद का मूल उद्देश्य आदिवासियों के हकों की सुरक्षा, उन्हें अपने अधिकार दिलाना, उन्हें 'शोषण' से मुक्त कराना और उनके अधिकारों के लिए 'शासन प्रशासन' से लड़ना रहा है। लेकिन यह काम करते करते जैसे जैसे नक्सल नेताओं के पास धन असला और सत्ता संग्रह होने लगा वैसे वैसे वे राज्य का स्वप्न देखने लगे चाहे उसके लिए

हिंसा का मार्ग ही क्यों न अपनाया पड़े। जहाँ तक स्थानीय लोगों के समर्थन की बात है, यह बात विवादों से घिरी है।



कुछ का मानना है कि नक्सलवाद को स्थानीय समर्थन तो है परन्तु वे इच्छा से नहीं बल्कि नक्सलियों के आतंक के डर के कारण है। आये दिन नक्सल नेता गाँव वालों से उनकी सुरक्षा के एवज में अपने परिवार का एक लड़का या लड़की नक्सल सेना में भर्ती के लिए माँग करते रहते हैं। नक्सल सेनाओं में लड़कियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक भी है। कटाक्ष के स्वर में नक्सल ये भी दावा करते हैं कि उन्हें बन्दूखें, असला पुलिस से और कभी कभी आयुध कारखानों से मिल जाते हैं। पुलिस गाँववासियों को सुरक्षा देने के बजाय पूछताछ और जाँच के नाम पर तंग करती है। रात को नक्सली डराते धमकाते हैं तो दिन में पुलिस। पुलिस प्रशासन का समर्थन उन्हें नक्सलियों की जानकारी देने का प्रयास और 'शान्ति और अहिंसा की बात करते हुए कोई आदिवासी पकड़ा गया तो उसे ऐसी विभत्स सजा दी जाती है कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि वे किसी से बात भी करें। पुलिस प्रशासन को सब मालूम होते हुए भी वे न कुछ करने देते हैं और न ही कुछ कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के सलवा जुद्ध से हानि अधिक हुई, लाभ कम। जो सांसद

विधायक इन नक्सलप्रभावित क्षेत्रों से चुनकर आते हैं वे सीधा सीधा नक्सल नेताओं की आर्थिक माँगों की पूर्ति कर निर्वाचित होकर आते हैं। क्षेत्र के निर्माण कार्यों के ठेकेदार और अन्य व्यापारी भी इसी तरह नक्सलियों की माँग की पूर्ति करते हैं। सुदूर जंगल में पदस्थ वन विभाग के रेन्जरो और छोटे कर्मचारियों से नक्सल नेता अक्सर टकराते रहते हैं। परन्तु वे भी कोई जानकारी बाँटने में विवश हैं। यह चर्चा आम है कि वन कर्मचारी भी नक्सल नेताओं को उनका हिस्सा देते हैं और अपनी कमाई करते रहते हैं। राजनेताओं की असंवेदनशीलता, अनिष्ठा, प्रतिबद्धता का अभाव और वनवासियों का 'शोषण' उनको विकास की मुख्यधारा तथा प्रशासन तंत्र से अलग थलग कर दिया है। प्रशासन ने उनका विश्वास खो दिया है। नक्सलवादी गाँव और गाँववासियों की इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और उनका भावनात्मक 'शोषण' करते हैं। नक्सली नेताओं को पावर, पैसा तथा हथियार का चस्का लग गया है और अब वे सरकार से बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। नक्सल नेता जंगलों में नहीं रहते 'शहरों' में भव्य ए.सी. बंगलों में रहते हैं। वे मुख्यधारा से जुड़ने को तैयार नहीं हैं। हिंसा त्यागने को भी तैयार नहीं हैं। शोषण और हिंसा के माध्यम से ही सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, प्रजातन्त्र के माध्यम से नहीं।



बी.के. 'शान्तिदूतों' के भ्रमण का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर कितना प्रभाव पड़ा या पड़ेगा यह तो वक्त ही बताएगा परन्तु दन्तेवाड़ा काण्ड के 'शहीदों' को 'शान्तिदूतों' के सेल्यूट और श्रद्धांजलि तथा उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। सम्भवतः लगातार इस प्रकार की 'शान्ति यात्राएँ' नक्सल नेताओं में 'शान्ति, भाईचारा प्रेम और अहिंसा' का संदेश प्रसारित करने में सफल साबित हो। अभी तो यह समय के गर्भ में ही है।

लेखक पूर्व संचालक  
जनसम्पर्क तथा वर्तमान में मीडिया फेकल्टी है

ई.मेल-

**kcmouli37@gmail.com**